



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)

PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 674]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 24, 2008/पौष 3, 1930

No. 674]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 24, 2008/PAUSA 3, 1930

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2008

सा.का.नि. 888(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 610क, 610ख और 610ड. के साथ पठित धारा 25 की उप-धारा (5) और उप-धारा (8) तथा धारा 609 की उप-धारा (2) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कम्पनी विनियम 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम कम्पनी (संशोधन) विनियम, 2008 है।
- (2) ये 15 फरवरी, 2009 से प्रवृत्त होंगे।

2. कम्पनी विनियम, 1956 में विधियम 17 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(1) रजिस्ट्रार अधिनियम और तद्विना बनाए गए विनियमों द्वारा या अधीन अपेक्षित या प्राधिकृत या फाइल किए गए प्रत्येक आवेदन या ई-प्ररूप या दस्तावेज की परीक्षा करेगा या परीक्षा करवाएगा, जो कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में उसकी वेबसाइट: WWW.mca.gov.in पर इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदन और रजिस्ट्रीकरण या अभिलेख पर रखने या अनुसमर्थन के लिए में फाइल किए गए हैं या परिदत्त किए गए हैं ;

परंतु वह ई-प्ररूप जिसकी प्रकृति में सूचनात्मक रूप में पहचान की गई है और जिसे स्ट्रेट ओ प्रोसेस (एसटीपी) फाइल किया गया है, किसी समय रजिस्ट्रार द्वारा जांच की जा सकेगी।

(2) जहां रजिस्ट्रार उप विनियम (1) में निर्दिष्ट किसी ऐसे आवेदन या ई-प्ररूप या दस्तावेज की जांच करने पर यह आवश्यक पाता है कि और जानकारी मांगे या ऐसे आवेदन या ई-प्ररूप या दस्तावेज को त्रुटिपूर्ण या किसी भी बाबत अपूर्ण पाता है वहां वह ऐसे व्यक्ति या कम्पनी के जिसने ऐसा आवेदन या ई-प्ररूप या दस्तावेज फाइल किया है वेबसाइट पर प्रस्तुत करके और अंतिम सूचित ई-मेल पते पर ई-मेल द्वारा ऐसी मांगी गई जानकारी या त्रुटि अपूर्णता की इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचना देगा और उसमें उसे या इसको यह निदेश देगा कि वह ऐसी जानकारी दे या ऐसी त्रुटि या अपूर्णता को ठीक करे या ऐसे आवेदन या ई-प्ररूप या दस्तावेज को पुनः प्रस्तुत करे;

परंतु यदि प्रश्नगत व्यक्ति या कम्पनी का ई-मेल पता उपलब्ध नहीं है तो ऐसी सूचना रजिस्ट्रार द्वारा यथास्थिति ऐसे व्यक्ति या कम्पनी के बताए गए अंतिम पते पर रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर डाक से दी जाएगी। रजिस्ट्रार ऐसी जानकारी के तथ्यों को इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में सुरक्षित रखेगा।

(3) जैसा कि इस अधिनियम में उपबंधित है उसके सिवाय रजिस्ट्रार ऐसे व्यक्ति या ऐसी कंपनी को जिसने ऐसा आवेदन या ई-प्ररूप या दस्तावेज फाइल किया है, तीस दिन का समय अनुज्ञात करते हुए ऐसे आवेदन या ई-प्ररूप या दस्तावेज के संबंध में और जानकारी देने के लिए या त्रुटि अथवा अपूर्णता को ठीक करने के लिए या ऐसा आवेदन या ई-प्ररूप या दस्तावेज पुनः प्रस्तुत करने के लिए अवसर देगा :

परंतु यह कि अधिनियम की धारा 18 (1) (क) और (ख) के अधीन फाइल किए गए ई-प्ररूप या दस्तावेज के संबंध में और जानकारी प्रस्तुत करने या त्रुटि अथवा अपूर्णता को दूर करने या पुनः प्रस्तुत करने के लिए केवल पंद्रह दिन का समय अनुज्ञात करेगा ।

(4) उस दशा में जब मांगी गई ऐसी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है या आंशिक रूप से प्रस्तुत की गई है या रजिस्ट्रार के समाधानप्रद रूप से उपलब्ध नहीं कराई गई है या त्रुटियां या अपूर्णता को ठीक नहीं किया गया है या आंशिक रूप से ठीक किया गया है या रजिस्ट्रार के समाधानप्रद रूप से उपविनियम (3) के अधीन अवसर उपलब्ध कराए जाने के बावजूद ठीक नहीं किया गया है तो रजिस्ट्रार यथास्थिति ऐसे आवेदन या ई-प्ररूप या दस्तावेज को “अविद्यमान्य रूप में” अभिलेख में अस्वीकृत कर देगा या उसका उपचार करेगा या उसे लेबल करेगा और ऐसे अविद्यमान्य आवेदन या ई-प्ररूप या दस्तावेज को अभिलेख पर नहीं लेगा तथा यथास्थिति ऐसे व्यक्ति या कंपनी को तदनुसार उपविनियम (2) में यथाविनिर्दिष्ट रीति में सूचित करेगा ।

(5) जहां किसी दस्तावेज को रजिस्ट्रार द्वारा अविद्यमान्य रूप में अभिलिखित किया गया है वहां ऐसा दस्तावेज कंपनी द्वारा केवल नए सिरे से फीस के संदाय के साथ और यथा लागू अतिरिक्त फीस के साथ अधिनियम के अधीन किसी अन्य दायिता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना नए सिरे से फाइल करके ठीक किया जाएगा ।

(6) जैसा अधिनियम में उपबंधित है उसके सिवाय रजिस्ट्रार किसी दस्तावेज को अनुमोदन और रजिस्ट्रीकरण के लिए या अभिलेख पर लेने के लिए या अस्वीकृत या अन्यथा के लिए फाइल किए जाने की तारीख से एक सौ बीस दिन से अनधिक के लिए उन मामलों को छोड़कर जिनमें केन्द्रीय सरकार या प्रादेशिक निदेशक या कंपनी विधि बोर्ड या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित है लंबित नहीं रखेगा ।

(7) यदि रजिस्ट्रार उपविनियम (1) के अधीन परंतुक में निर्दिष्ट स्ट्रेट थ्रो प्रोसेस (एसटीपी) के अधीन फाइल किए गए किसी ई-प्ररूप या दस्तावेज को किसी समय किसी भी बाबत त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण पाता है तो वह इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री में ऐसे ई-प्ररूप या दस्तावेज को “त्रुटिपूर्ण” समझेगा और लेबल करेगा तथा ऐसे ई-प्ररूप या दस्तावेज में ऐसी त्रुटि या अपूर्णता को बताते हुए एक सूचना ऐसे व्यक्ति या कंपनी के अंतिम ज्ञात ई-मेल पते पर (यदि उपलब्ध हो), जिसने दस्तावेज फाइल किया है लिखित में डाक द्वारा ऐसे व्यक्ति के पते पर या ऐसी कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर जारी करेगा, जिसमें ऐसे व्यक्ति या कंपनी से यह मांग करेगा कि वह ऐसा ई-प्ररूप या दस्तावेज नए सिरे से फीस और अतिरिक्त फीस जो लागू हो सहित, ऐसी त्रुटि या अपूर्णता को ठीक करते हुए ऐसी सूचना की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर नए सिरे से फाइल करे ।

(8) रजिस्ट्रार साठ दिन की अवधि के भीतर प्रत्येक ई-प्ररूप या दस्तावेज को जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल किया गया है और इस कार्यालय में इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के प्रारंभ की तारीख को

फाइल किए जाने की तारीख से तीस दिन की अधिक की अवधि से लंबित है पुनःपरीक्षा करेगा, किसी भी बाबत त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण पाए जाने पर ऐसी त्रुटि या अपूर्णता को ऐसे आवेदन या ई-प्ररूप या दस्तावेज में पुनः वेबसाइट पर डालकर तथा ई-मेल द्वारा (यदि ई-मेल का पता उपलब्ध नहीं हो तो डाक द्वारा) उस व्यक्ति के बताए गए अंतिम पते पर या कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर, जिसने ऐसा आवेदन या दस्तावेज फाइल किया है, भेजेगा और उसे या इसको यह निदेश देगा कि ऐसी सूचना की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर ऐसी त्रुटियों या अपूर्णता को ठीक करके आवेदन या ई-प्ररूप या दस्तावेज को पुनः प्रस्तुत करेगा, जिसके न हो सकने पर ऐसा आवेदन या ई-प्ररूप या दस्तावेज अविधिमान्य समझा जाएगा और यथास्थिति अनुमोदित या रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा या अभिलेख पर नहीं लिया जाएगा :

परंतु उस दशा में जब ऐसा व्यक्ति या कंपनी उपविनियम में यथा उपबंधित समय के भीतर ऐसे आवेदन या ई-प्ररूप या दस्तावेज की त्रुटियों या अपूर्णताओं को ठीक करने या सभी बाबत ऐसे आवेदन या ई-प्ररूप या दस्तावेज को पुनः प्रस्तुत करने में असफल रहती है तो रजिस्ट्रार उसे या तो अस्वीकृत कर देगा या ऐसे आवेदन या ई-प्ररूप या दस्तावेज को अविधिमान्य समझे या लेबल करेगा और ऐसे अविधिमान्य आवेदन या ई-प्ररूप या दस्तावेज को अभिलेख में नहीं लेगा तथा ऐसे व्यक्ति या कंपनी को तदनुसार उस रीति में जिसमें इस उपविनियम में सूचना दी गई जाएगी:

परंतु यह और कि जैसा इस अधिनियम में उपबंधित है उसके सिवाय, रजिस्ट्रार इस उपविनियम में निर्दिष्ट किसी दस्तावेज को अनुमोदन और रजिस्ट्रीकरण या अभिलेख पर लिए जाने के लिए या अस्वीकृत करने के लिए या अन्यथा उपविनियम (6) में विनिर्दिष्ट मामलों को छोड़कर इन विनियमों के प्रारंभ की तारीख से एक सौ पचास दिन से अधिक अवधि के लिए लंबित नहीं रखेगा ।

[फा. सं. 1/8/2008 सीएलबी]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

टिप्पण :- मूल विनियम भारत के राजपत्र में का.नि.आ. 432ख तारीख 18.2.1956 द्वारा प्रकाशित किए गए और पश्चात्तर्वर्ती निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किया गया:-

क्रम सं.	अधिसूचना सं.	अधिसूचना तारीख
1.	सा0का0नि0 188	09-01-1958
2.	सा0का0नि0 399	24-03-1962
3.	सा0का0नि0 1850	01-12-1966
4.	सा0का0नि0 1445	16-09-1967
5.	सा0का0नि0 668	10-06-1973
6.	सा0का0नि0 523	11-07-1989
7.	सा0का0नि0 367(अ)	31.-05-1991
8.	सा0का0नि0 924(अ)	14-12-1992
9.	सा0का0नि0 610(अ)	23-12-2005
10.	सा0का0नि0 157(अ)	16-03-2006
11.	सा0का0नि0 497(अ)	21-08-2006
12.	सा0का0नि0 556(अ)	14-09-2006

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th December, 2008

G.S.R. 888(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (5) and (8) of section 25 and sub-section (2) of section 609 read with sections 610A, 610B and 610E of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Companies Regulations, 1956, namely :-

1. (1) These Regulations may be called the Companies (Amendment) Regulations, 2008.

(2) They shall come into force with effect from 15th February, 2009.

2. In the Companies Regulations, 1956, for regulation 17, the following shall be substituted namely:-

“(1) The Registrar shall examine or cause to be examined, every application or e-Form or document required or authorised or filed by or under the Act and rules made thereunder, filed with or delivered to, in the electronic form, the Ministry of Corporate Affairs on its website www.mca.gov.in, for approval and registration or taking on record or rectification by the Registrar:

Provided that the e-Forms identified as informative in nature and filed under Straight Through Process (STP) may be examined by the Registrar any time.

(2) Where the Registrar, on examining any such application or e-Form or document referred to in sub-regulation (1), finds it necessary to call further information or finds such application or e-Form or document to be defective or incomplete in any respect, he shall give intimation of such information called for or defect or incompleteness noticed electronically, by placing it on the website and by e-mail on the last intimated e-mail address of the person or the company, which has filed such application or e-Form or document, directing him or it to furnish such information or to rectify such defects or incompleteness or to re-submit such application or e-Form or document:

Provided that in case the e-mail address of the person or company in question is not available, such intimation shall be given by the Registrar by post at the last intimated address or registered office of such person or company as the case may be. The Registrar shall preserve the facts of such intimation in the electronic record.

(3) Except as otherwise provided in the Act, the Registrar shall give an opportunity allowing thirty days time to such person or such company which has filed such application or e-Form or document, for furnishing further information or for rectification of the defects or incompleteness or for re-submission of such application or e-Form or document:

Provided that he shall allow fifteen days time only, for furnishing further information or for rectification of the defects or incompleteness or for re-submission of e-Form or documents filed under section 18(1) (a) and (b) of the Act.

(4) In the event, such further information called for has not been provided or has been furnished partially or has not been provided to the satisfaction of the Registrar or defect or incompleteness has not been rectified or has been rectified partially or has not

been rectified to the satisfaction of the Registrar, despite opportunity provided under sub-regulation (3), the Registrar shall either reject or treat and label such application or e-Form or document as the case may be as “invalid” in the electronic record, and shall not take on record such invalid application or e-Form or document and shall inform such person or company, as the case may be, accordingly in the mode, as specified in sub-regulation (2).

(5) Where any document has been recorded as invalid by the Registrar, such document may be rectified by the company only through fresh filing with payment of fee and additional fee as applicable, without prejudice to any other liability under the Act.

(6) Except as otherwise provided in the Act, the Registrar shall not keep any document pending for approval and registration or for taking on record or for rejection or otherwise for more than one hundred twenty days, from the date of its filing excluding the cases in which an approval from the Central Government or Regional Director or Company Law Board or any other competent authority is required.

(7) The Registrar, in case, finds any such e-Form or document filed under Straight Through Process (STP), referred in proviso under sub-regulation (1), as defective or incomplete in any respect, at any time, he shall treat and label such e-Form or document as “defective” in the electronic registry and shall issue a notice pointing out such defects or incompleteness in such e-form or document at the last intimated e-mail address (if available) of the person or the company which has filed the document and in writing by post at the address of such person or registered office address of such company, calling upon such person or company to file such e-form or document afresh

with fee and additional fee as applicable, after rectifying such defects or incompleteness within a period of thirty days from the date of such notice.

(8) The Registrar shall re-examine, within a period of sixty days, every application or e-Form or document filed electronically and pending in his office for more than thirty days from the date of filing as on the date of commencement of these regulations, found as defective or incomplete in any respect, and shall intimate such defects or incompleteness in such application or e-Form or document, by placing them on the web site, and by e-mail (in case e-mail address is not available, then by post) on the last intimated address of the person or registered office address of the company which has filed such application or document directing him or it to rectify such defects or incompleteness or to re-submit the application or e-Form or document within a period of thirty days from the date of such intimation, failing which such application or e-Form or document shall be treated as invalid and shall not be approved or registered or taken on record, as the case may be:

Provided that in case such person or company fails to rectify the defects or incompleteness or to re-submit such application or e-Form or document complete in all respect within the time provided in this sub-regulation, the Registrar shall either reject the same or treat and label such application or e-Form or document as invalid and shall not take on record such invalid application or e-Form or document, and such person or company shall be informed accordingly in the mode in which intimation was given in this sub-regulation:

Provided further that, except as otherwise provided in the Act, the Registrar shall not keep any document, referred in this sub-regulation, pending for approval and

registration or for taking on record or for rejection or otherwise for more than one hundred fifty days from the date of commencement of these regulations excluding the cases as specified in sub-regulation (6) ”.

[F. No. 1/8/2008.CLV]

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.

Note:— The principal regulations were published in the Gazette of India vide number SRO 432B dated 18-2-1956 and subsequent amended by the following notifications:-

S.no.	Notification number	Notification date
1	G.S.R. 188	09-01-1958
2	G.S.R. 399	24-03-1962
3	G.S.R. 1850	01-12-1966
4	G.S.R. 1445	16-09- 1967
5	G.S.R. 668	10-06- 1973
6	G.S.R. 523	11-07- 1989
7	S.O. 367(E)	31-05- 1991
8	G.S.R. 924(E)	14-12- 1992
9	G.S.R. 610(E)	23-12- 2005
10	G.S.R. 157(E)	16-03- 2006
11	G.S.R. 497(E)	21-08- 2006
12	G.S.R 556(E)	14-09- 2006.